निवेश के लिए नीतियां ही नहीं, ईको सिस्टम भी जरूरी

जीसीसी कॉन्क्लेव : मुख्य सचिव ने कहा- प्रदेश में पहले भी उद्योग थे, लेकिन निवेशकों में आज जैसा आकर्षण नहीं था

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सिर्फ औद्योगिक नीतियों से निवेश नहीं आता और न ही नीतियों के अभाव में निवेश जाता है। किसी राज्य में पैसा लगाने से पहले निवेशक बहुत कुछ देखता है, इसलिए नीतियों के साथ औद्योगिक ईकोसिस्टम का होना बहुत जरूरी है। इसे यूपी ने कर दिखाया है।

इसी का नतीजा है कि आज दुनियाभर से निवेशक यहां आना चाहते हैं। वे मंगलवार को गोमती नगर स्थित एक होटल में वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) कॉन्क्लेव में बोल रहे थे।

राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट यूपी ने जीसीसी नीति-2024 के तहत निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित इस कॉन्क्लेव में मुख्य सचिव ने कहा कि पहले भी इंडस्ट्रीज थीं, लेकिन आज जैसा आकर्षण नहीं था। पहले पॉलिसी थी, लेकिन इंसेंटिव नहीं मिलता था। निवेशक कहते थे कि पॉलिसी के तहत इंसेटिव देने के समय पीछे हो जाते हैं। यूपी ने इस धारणा को बदला है।

उन्होंने कहा कि पहले यूपी हमेशा दूसरा विकल्प था। अब पहले विकल्प के रूप में हम काम कर रहे हैं। पिछले सात-आठ साल में अपनी जीडीपी को दोगुना करने वाले उदाहरण दुनिया में बहुत कम हैं। इस दौरान यूपी की आबादी में चार करोड़ नए लोग भी शामिल हुए हैं।

गोमतीनगर स्थित एक होटल में जीसीसी कॉन्क्लेव को संबोधित करते मुख्य सचिव मनोज सिंह। -संवाद

प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी होकर 600 डॉलर से 1400 डॉलर हो गई, लेकिन अब भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। टियर टू और टियर थ्री शहरों पर फोकस किया जा रहा है। आजादी के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा बसे। अब बुंदेलखंड में 65000 एकड़ में नया शहर बनाया जा रहा है। अब तक 18000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो चुका है।

कॉन्क्लेव में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद, टीसीएस लखनऊ के अमिताभ तिवारी, नासकॉम के रीजनल हेड अमित वर्मा, यूपीडेस्को की प्रबंध निदेशक नेहा जैन, आवास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद, इन्वेस्ट यूपी के एसीईओ शशांक चौधरी और एडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार भी शामिल हुए।

विकसित राज्य के बिना विकसित राष्ट्र का लक्ष्य संभव नहीं

प्रमुख सचिव एमएसएमई और अवस्थापना आलोक कुमार ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य विकसित राज्य के बिना संभव नहीं है। पिछले कुछ सालों में यूपी में बड़े बदलाव हुए हैं। यहां सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क, सड़क नेटवर्क, रेल नेटवर्क और सबसे बड़ी वर्कफोर्स है। वर्ष 2015 तक प्रदेश में मात्र 500 फैक्टरी पंजीकृत थीं। आज दस साल में ये संख्या 4000 हो गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़त प्राप्त है, लेकिन सर्विस सेक्टर में क्षमताओं के अनुरूप काम नहीं हुआ है। नोएडा, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहर सर्विस सेक्टर का गढ़ बन सकते हैं। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने प्रदेश की नीतियों और बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी दी।

अमेरिका और यूरोप में होंगे रोड शो

प्रदेश सरकार ने ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर (जीसीसी) पॉलिसी के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़े स्तर पर योजना तैयार की है। कई कंपनियों ने आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जीसीसी में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। बेंगलूरु, चेन्नई और हैदराबाद में रोड शो के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के शहरों में रोड शो किया जाएगा। कॉन्क्लेव के दौरान चर्चा चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रही। रियल एस्टेट और वाणिज्यिक स्थान, जिसमें क्रेडई और आगामी बिल्डिंग बाइलॉज शामिल है।

गुणवत्तापूर्ण कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों द्वारा समर्थित कुशल व प्रतिभावान कार्यबल की उपलब्धता, संपूर्ण कारोबारी पारिस्थितिकी तंत्र और बुनियादी ढांचे में सुधार। कॉन्क्लेव में करीब 20 कंपनियों ने इस आयोजन में भाग लिया। जिनमें एसआरके गेमचेंजर्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, टीसीएस, ट्राइडेंट ग्रुप, वेलोसिस सिस्टम्स, डेलॉयट, यूएस इंडिया, एचसीएल, माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख रहीं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के स्ट्रैटेजी व ऑपरेशन्स लीड वरुण रामनन ने हैदराबाद से नोएडा तक कंपनी के विस्तार पर प्रकाश डाला। नैस्कॉम के उत्तर भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अमित वर्मा ने उत्तर प्रदेश के विकसित होते जीसीसी इकोसिस्टम के बारे में जानकारी दी। एमएक्यू सॉफ्टवेयर के संस्थापक राजीव अग्रवाल ने यूपी के तकनीकी-आधारित बिजनेस हब के रूप में प्रतिस्पर्धा के बारे में जानकारी दी।